लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 1-15 मार्च 2021 www.haryanasamvad.gov.in अंक -13

"विलुप्त सरस्वती नदी का उद्गम स्थल यमुनानगर के आदिबद्री नामक स्थान को माना जाता है।

: महाभारत

बदलते गांव, बदलता हरियाणा

3

शिवालिक की पहाड़ियों में गुलाब की खेती

5

महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता

7

सुशासन में सफल रही सहयोगियों की भूमिका

विशेष प्रतिनिधि

शासन-प्रशासन के कामकाज को पारदर्शी एवं गतिशील रखने के लिए सुशासन सहयोगियों की भूमिका सराहनीय रही है। एक मायने में राज्य सरकार का यह अनूठा प्रयोग सफल एवं अनुकरणीय है। केंद्र व राज्य सरकार की अनेक योजनाओं को ये अधिकारी जमीनी स्तर तक ले गए जिससे प्रदेश के जनता को उनका फायदा मिला।

प्रदेश सरकार का उद्देश्य न केवल अंत्योदय के विजन को साकार करना है बल्कि जन-जन तक यह संदेश पहुंचाना भी है कि सरकार पर सबसे पहला अधिकार जरूरतमंद व्यक्ति का है। इसी दिशा में बढ़ते हुए सरकार ने अपनी तरह की पहली महत्वाकांक्षी योजना 'परिवार पहचान पत्र' को लागू किया है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को मिले।

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने हाल ही में सुशासन सहयोगियों की बैठक ली जिसमें सरकार की विशेष योजनाओं जैसे परिवार पहचान पत्र, ई-ऑफिस, अंत्योदय सरल, प्ले-वे स्कूल, महिलाओं की सुरक्षा, सक्षम हरियाणा व स्किल डेवलपमेंट इत्यादि पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि गत पांच वर्षों से सीएमजीजीए कार्यक्रम जमीनी स्तर पर सकारात्मक परिणाम देता रहा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान आए संकट की घड़ी में भी सभी सुशासन सहयोगियों ने बेहतरीन कार्य किया है जो सराहनीय है।

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने कहा कि पांच वर्ष पहले शुरू हुआ मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम अभिनव व अनूठा प्रयोग है और इसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं।

ई-ऑफिस के सफल क्रियान्वयन पर प्रकाश डालते हुए सुशासन सहयोगियों ने बताया कि ई-ऑफिस के लिए 18,000 सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। 80 से ज्यादा विभाग और 800 से अधिक जिला कार्यालय अब ई-ऑफिस पर आ गए हैं। ई-ऑफिस पर अब तक एक लाख से अधिक फाइलें और 3 लाख से अधिक ई- रसीद 15 लाख से भी अधिक बार मूव हुई हैं। राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर सभी सरकारी कार्यालयों में 95 प्रतिशत से अधिक लोगों ने पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए फाइलों का डिजिटल प्रसंस्करण शुरू किया है।

कौशल की गुणवत्ता में सुधार लाने और युवाओं को रोजगार व अप्रेंटिशिप के अवसरों से जोड़ने के लिए भी कार्य किए गए। दोहरी प्रणाली प्रशिक्षण (डीएसटी) के माध्यम से 3,700 से अधिक आईटीआई छात्रों को उनके कौशल से संबंधित व्यावहारिक उद्योग का अनुभव प्रदान करने के लिए 100 से अधिक उद्योग पार्टनर्स के साथ 175 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

ताकि सशक्त हो गरीब परिवार

एक अप्रैल 2021 से एक अनूठी योजना को क्रियान्वित किया जाएगा जिसके तहत परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर प्रदेश में सबसे कम पारिवारिक आय वाले ऐसे एक लाख गरीब परिवारों का चयन किया जाएगा, जिनकी पारिवारिक आय एक लाख से कम है। ऐसे परिवारों की आय को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ऐसे परिवारों के सदस्यों का कौशल विकास करने, जिनके पास रोजगार नहीं है उन्हें निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने और वित्तीय सहायता प्रदान करने पर जोर दे रही है। साथ ही, सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत रोजगार देने के साथ-साथ यदि किसी परिवार का कोई पैतृक कार्य है तो उसे प्रोत्साहन देने के लिए भी सरकार द्वारा सहयोग किया जाएगा।

किसान मित्र योजना

प्रदेश सरकार छोटी जोत के किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। आय बढ़ने के साथ-साथ किसानों का वित्तीय प्रबंधन सही हो इसके लिए सरकार 'किसान मित्र योजना' की तैयारी है। इसके तहत एक व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से आगे 100 किसानों को वित्तीय प्रबंधन के बारे में बताएगा।

वन मित्र योजना

विकास के साथ-साथ पर्यावरण को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार 'वन मित्र योजना' लाने की तैयारी में है। इस योजना के तहत व्यक्ति नए पेड़ लगाएगा और पेड़ों की देखरेख व सुरक्षा करेगा।

खेलों को बढ़ावा

हरियाणा राज्य खेल हब बन रहा है। प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हर गांव में योग व व्यायामशालाएं बनाई जा रही हैं। इनके साथ वैलनेस सेंटरों की मदद रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'फिट इंडिया' की कल्पना की थी ताकि हर व्यक्ति तंदुरुस्त रहे।

अनिल विज सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री

हरियाणा को 'बैस्ट स्टेट इन हेल्थ' का स्कॉच अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही बतौर स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज को देश के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का खिताब मिला है। यह अवार्ड प्रदेश तथा जिला स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक उत्कृष्ट शुरूआत करने के लिए दिया गया है।

विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा एवं आयुष विभाग के निदेशक श्री प्रभजोत सिंह तथा स्वास्थ्य महानिदेशक श्री सुरजभान कम्बोज ने इन स्कॉच पुरस्कारों के प्रशस्ति पत्र स्वास्थ्य मंत्री को भेंट किए। उन्होंने कहा कि स्कॉच नामक निजी संस्था द्वारा देशभर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर अनुसंधान एवं मूल्यांकन किया गया, जिसमें पाया गया कि हरियाणा ने देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है। इनमें कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा है।

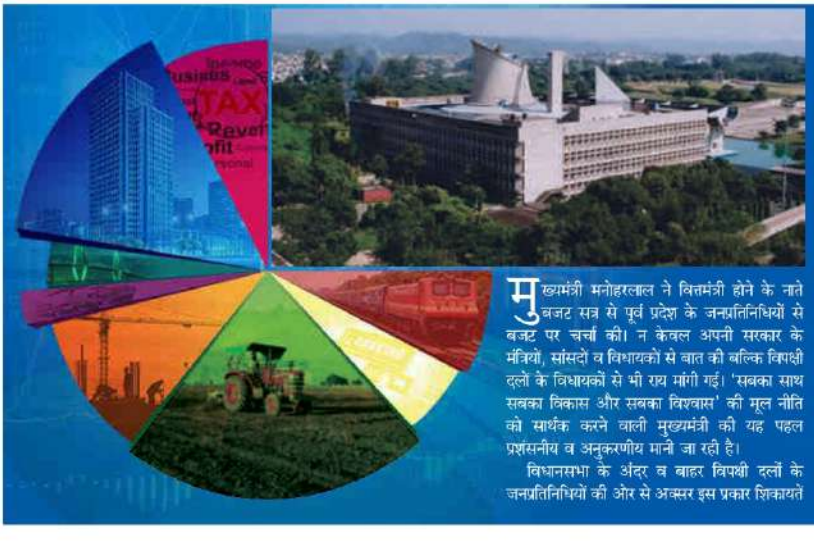

सत्र से पूर्व बजट पर चर्चा

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने वित्तमंत्री होने के नाते बजट सत्र से पूर्व प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से बजट पर चर्चा की। न केवल अपनी सरकार के मंत्रियों, सांसदों व विधायकों से बात की बल्कि विपक्षी दलों के विधायकों से भी राय मांगी गई। 'सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास' की मूल नीति को सार्थक करने वाली मुख्यमंत्री की यह पहल प्रशंसनीय व अनुकरणीय मानी जा रही है।

विधानसभा के अंदर व बाहर विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधियों की ओर से अक्सर इस प्रकार शिकायतें रही है कि राज्य सरकार ने विकास कार्यों में भेदभाव किया, निष्पक्षता नहीं बरती गई। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल में बजट सत्र की रूपरेखा में परिवर्तन करते हुए इस प्रकार की शिकायतबाजी के अवसरों को समाप्त करने का काम किया है। गत वर्ष भी सभी जन प्रतिनिधियों से बजट से पूर्व राय ली गई थी।

वित्तमंत्री की ओर से पांच मार्च को बजट पेश किया जा रहा है। प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए अनेक योजनाओं का प्रारूप सत्र में पेश होगा। पिछले वर्ष डेढ़ करोड़ का बजट पेश किया गया था। कोरोना की वजह से गत वर्ष प्रदेश को 12 हजार करोड़ का कम राजस्व प्राप्त हुआ है लेकिन माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री मनोहरलाल विकास की गति को बनाए रखने के लिए कोई कंजूसी नहीं बरतेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि क्षेत्र के बजट में बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

वित्तमंत्री के पिटारे में वैसे तो बहुत कुछ होगा मगर कुछ स्कीम ऐसे हो सकती है जो अलग हटके होंगी। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार बुढ़ापा पेंशन की तर्ज पर कैंसर, एचआईवी पॉजिटिव व किडनी के मरीजों को भी 2250 रुपए मासिक पेंशन देने जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओमप्रकाश यादव के अनुसार यह एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। इससे गंभीर बीमारी का शिकार लोगों को लाभ मिलेगा। पिछले साल के दौरान कोरोना के कारण यह योजना लागू नहीं की जा सकी, लेकिन अब इसे लागू किया जाएगा। तीनों श्रेणियों के करीब 25 हजार रोगियों को चिन्हित किया जा चुका है।

निदेशक श्री प्रभजोत सिंह ने बताया कि एनएचएम के लिए बजट वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए 944.63 करोड़ रुपए था। यह बढ़ने की संभावना है क्योंकि किफायती दरों पर प्रमुख चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। एनएचएम की हरियाणा में 200 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने की भी योजना है।

मनोज प्रभाकर

संपादकीय

सभी क्षेत्रों से सुखद हैं ख़बरें

हरियाणा, समय-समय पर अपनी उपलब्धियों का लेखा-जोखा करता रहता है। इस वर्ष का बजट इसी दिशा की एक महत्त्वपूर्ण पहलकदमी सिद्ध होगा। यह श्रेय भी यहां के ग्रामीणों एवं किसानों को जाता है कि किसान आंदोलन के बावजूद खेती का सिलसिला कहीं भी टूटने नहीं दिया गया।

शिक्षा व कुछेक कामधंधे 'ऑनलाइन' चले, मगर कहीं कोई भी काम-काज ठप्प नहीं हुआ। विश्वविद्यालयों, कालेजों व स्कूलों में सक्रियता फिर से बहाल होने लगी है।

कला-संस्कृति व साहित्य के मोर्चे पर भी विकास एवं उपलब्धियों का सिलसिला जारी है। तीन वर्षों से लंबित साहित्यकार-सम्मानों की घोषणा, सरस्वती महोत्सव और विकट भविष्य में 'लिट फैस्ट' अर्थात् राष्ट्रीय स्तर के 'साहित्य पर्व' की योजना पर काम जारी है।

ज़िंदगी कहीं भी थमीं नहीं। अस्पतालों में मुस्तैदी बढ़ी है। इधर शहरीकरण के साथ-साथ अब ग्रामों में भी आवास योजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति के लिए गंभीर प्रयास जारी हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक पहल की गई हैं जिनका परिणाम आने लगा है। खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार ने ओलंपिक की तैयारियों के लिए खिलाड़ियों को पांच पांच लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। जो काफी सराहनीय है।

एक सुखद निर्णय यह भी है कि कुछ बरसों से रुके हुए पर्यटन-विकास पर अब विशेष ध्यान दिया जा रहा है। करनाल को प्रदेश का प्रमुख 'पर्यटन हब' बनाने की घोषणा की गई है।

निष्कर्ष यह कि लगभग हर क्षेत्र में सक्रियता बढ़ी है और प्रदेश धीरे-धीरे बेहतर जीवन की ओर अग्रसर हो रहा है।

- डा. चंद्र त्रिखा

आईएमटी मानेसर को समृद्ध बनाने की तैयारी

आईएमटी मानेसर में व्यवस्थाएं और बेहतर हों इसके लिए राज्य सरकार काम कर रही है। मध्यम और सूक्ष्म इकाईयों के लिए एमएसएमई विभाग बनाया गया है ताकि उन्हें ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

गुरुग्राम में आईएमटी मानेसर के उद्यमियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने बताया कि मानेसर को मेट्रो रेल से जोड़ने के लिए 8 हजार करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की जा रही है। मेट्रो रेल लाइन मानेसर होते हुए बावल तक बनेगी। 14.80 करोड़ रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी।

मानेसर क्षेत्र में 100 बैड का अस्पताल बनाया जाएगा। अस्पताल बनने तक स्वास्थ्य विभाग यहां अस्थाई डिस्पेंसरी की व्यवस्था करवाएगा। मानेसर क्षेत्र में महिला पुलिस थाना खोला जाएगा। उद्यमियों की मांग पर वहां पर 200 तक एफएआर मंजूर किया जाएगा। फायर एनओसी लेने की प्रक्रिया के साथ-साथ सरलीकरण किया जाएगा, 18 फीट ऊंचाई के भवनों को फायर एनओसी प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।

मानेसर के उद्यमियों के लिए परेशानी का सबब बना खेड़कीदौला टोल प्लाजा अगले छह महीने के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। मानेसर क्षेत्र के 29 गांवों को शामिल करके मानेसर नगर निगम बनाया गया है। नगर निगम की वार्डबंदी होगी और फिर चुनाव होंगे। चुनाव होने तक प्रशासनिक कार्य नगर निगम के आयुक्त देखेंगे। नगर निगम, मानेसर बनने के बाद अब इस क्षेत्र में सीवरेज, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, सड़क, पार्क, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार, बागवानी संबंधी कार्य, पेयजल व्यवस्था आदि के समुचित प्रबंध किए जाएंगे।

12 परिवारों को आवंटीय प्लॉट

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने बादशाहपुर में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से लोगों के पुनर्वास के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत दौलताबाद के 12 परिवारों को प्लॉट के अलॉटमेंट लेटर वितरित किए। इन सभी 12 परिवारों को गुरुग्राम के सेक्टर-48 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से उप्पल साउथ एंड कॉलोनी में प्लॉट दिए गए हैं।

संवाद ब्यूरो

दौलताबाद में नए संस्थान की आधारशिला

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने गांव दौलताबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एवं एग्रीप्रेन्योरशिप नामक संस्थान की आधारशिला रखी। इस संस्थान का निर्माण चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संस्थान हरियाणा प्रदेश में तो अनूठा होगा ही, देश में भी इसके मुकाबले का संस्थान नहीं होगा। इस संस्थान के माध्यम से कृषि उत्पादों को बेचने और उनके प्रबंधन के पूरे अवसर मिलेंगे।

उन्होंने कहा बीज से लेकर बाजार तक के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। सरकार का प्रयास है कि हर किसान की ट्रैकिंग की जाए कि उसे समय पर बीज व खाद बाजार में ठीक भाव में मिले ताकि प्रदेश का किसान खुशहाल हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली एनसीआर की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान सब्जी, फल, फूल, दूध, मछली पालन, दुग्ध उत्पाद आदि के उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान दें।

ई-संजीवनी से लें घर बैठे उपचार

स्वास्थ्य विभाग द्वारा ई-संजीवनी ओपीडी सेवा शुरू की गई है, जिसके माध्यम से नागरिक घर बैठे इलाज ले सकते हैं। सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तथा सायं 3 बजे से 5 बजे तक स्वास्थ्य संबंधित परामर्श ले सकते हैं।

यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं या फिर गर्भवती महिला हैं तो आपको थोड़ी-बहुत तकलीफ होने पर उपचार के लिए अब नागरिक अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिला स्तर पर ई-संजीवनी ओपीडी शुरू की है। ई-संजीवनी एप के माध्यम से घर बैठे ही संबंधित बीमारी के बारे में डॉक्टर से परामर्श लिया जा सकता है।

इसके लिए मरीज को अपने एंड्रायड फोन पर ई-संजीवनी एप्प डाउनलोड करना होगा। इसके बाद एप पर ही अपने मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन कर अपनी तकलीफ बतानी होगी। इस सेवा का लाभ लेने के लिए नागरिकों को अपने स्मार्ट फोन से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिसके बाद वीडियो कॉलिंग या वेब कैमरे के जरिये रोगी से चिकित्सक बात करके उचित दवाई बताएंगे। संबंधित डॉक्टर टैलीकॉन्सल्टेशन के जरिये मरीज से बात करेगा और उसे क्या-क्या एहतियात बरतनी है इन सबके बारे में परामर्श तो देगा ही। इसके साथ-साथ उसे कौन सी दवाई की आवश्यकता है इसके बारे में भी बताएगा।

रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि डॉक्टर मरीज से उसकी समस्याएं जानकर उपचार के लिए दवाइयां लिख देगा। दवाई की पर्ची को मरीज डाउनलोड करने के उपरांत सामान्य अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर दवाइयां प्राप्त कर सकेगा। उन्होंने कहा कि रोगी को लैब टेस्ट या दवाइयों की पर्ची डॉक्टर द्वारा ऑनलाइन प्रदान की जाएगी।

ई-संजीवनी के नोडल अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार मलिक ने बताया कि सामान्य अस्पताल रोहतक में ई-संजीवनी की सेवाएं आरंभ की जा चुकी है। इसके लिए अलग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम स्थापित किया गया है। विभिन्न रोगों के 15 चिकित्सा विशेषज्ञों को ऐप रजिस्टर्ड किया जा चुका है।

कर्ण लेक के सौंदर्यीकरण की तैयारी

करनाल की कर्ण लेक को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके सौंदर्यीकरण पर करीब 7 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कार्य अगले एक वर्ष पूरा हो जाने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने हाल ही में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जिसमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ी योजनओं को स्वकृति प्रदान की गई। इन योजनाओं में लेक का सौंदर्यकरण शामिल है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कर्ण लेक की ओर अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। पर्यटकों व आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखा जाए। इसके लिए दो प्रवेश द्वार रखे जाएं और वहीं पर टिकट काउंटर की व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि करनाल शहर के लोगों के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक तथा सायं 7 बजे से 9 बजे तक लेक पर भ्रमण करने की व्यवस्था निशुल्क करवाई जाए।

उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लेक में स्वच्छ जल के लिए नहर से व्यवस्था करवाएं। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि भाखड़ा चैनल से एक क्यूसिक पानी लेक में छोड़ा जाता है, इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पानी को बढ़ाकर 3 क्यूसिक किया जाए।

करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उपायुक्त श्री निशांत कुमार यादव ने कर्ण लेक के सौंदर्यीकरण को लेकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत तैयार किए गए प्लान की प्रजेंटेशन दी।

उन्होंने बताया कि कर्ण लेक की 1.26 किलोमीटर पैरिफेरी को विकसित किया जाएगा। कर्ण लेक की पैरिफेरी में साईनेज, पाथ-वे, लाईटिंग व साईकिल ट्रैक बनाया जाएगा। झील में वर्षभर पानी मौजूद रहे इसके लिए दो नलकूप लगेंगे, फूड कोर्ट और कैफे बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि झील के अंदर मौजूद एक आईलैंड यानि टापू को विकसित कर वहां स्कल्पचर वॉक बनाएंगे, जिसमें महाभारत जैसे थीम पर मूर्तियां लगाई जाएंगी। झील के अंदर ही संगीतमयी फव्वारा लगेगा और किनारे पर व्यू डैक बनाए जाएंगे। इन सब प्रयासों के परिणामस्वरूप स्थानीय व बाहरी दस्तकार यहां आकर अपना सामान बेच सकेंगे। इससे उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे और विभाग के लिए आय के स्रोत भी बढ़ेंगे।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
संपादकीय टीम : संगीता शर्मा, सुरेंद्र मलिक, मनोज चौहान
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

'हरियाणा उद्यम एवं रोज़गार नीति 2020' के तहत लाइसेंस नवीनीकरण की आवश्यकता को समाप्त करके अनुपालन बोझ को कम किया गया है। नारनौल में एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित किया जा रहा है।

प्रदेश से लगभग 85,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया जा रहा है, जिसमें बासमती, आईटी और ऑटोमोबाइल पार्टस शामिल हैं। निर्यात बढ़ाने के लिए एक जिला-एक उत्पाद योजना के तहत 32 उत्पादों की पहचान की गई है।

बदलते गांव, बदलता हरियाणा

मनोज प्रभाकर

गांव तेजी से बदल रहे हैं। विकास की भागमभाग में ग्राम संस्कृति की अनेक समृद्ध परंपराएं बिना किसी प्रतिकार के इतिहास बनती जा रही हैं। आधुनिकता की दौड़ में लोगों ने रहन-सहन के तौर तरीके बदल लिए हैं। गांव में अब न कोई कच्चा मकान दिखाई देता है और न कोई गली कच्ची दिखाई देती है।

गांवों की फिरनी से बाहर खेतों में शहरी तर्ज पर खुले और बड़े मकान बनाने की परंपरा शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं बहुत से मकानों के आंगन में कारें, ट्रैक्टर, बाइक व अन्य वाहन खड़े दिखाई देते हैं। खेतों में पगडंडियों की जगह पक्की सड़क व ऊंचे-ऊंचे शानदार मकान देखकर लगता है कि गांव अब किसी नई राह पर है।

प्रदेश में गांवों की संख्या लगभग 6,200 से ज़्यादा है। राज्य सरकार के मुताबिक पांच हजार से ज्यादा गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। बात बहुत पुरानी नहीं है। कुछ वर्ष पहले तक गांव में तीन दिन के बाद बिजली आती थी। जिस दिन बिजली आती उस दिन आटा चक्की चलती और गंडासे पर पशुओं के लिए हरा चारा काटा जाता। पानी भी उसी दिन मोटर से भरा जाता। इतना ही नहीं जो पशुपालक बिजली पर निर्भर थे वे तीन-तीन दिन का दूध एक दिन बिजली आने पर बिलावणी में बिलोते थे और नूणी घी व छाछ निकालते थे। छोटे मोटे कुटीर उद्योगों ने भी बिजली की इस आपूर्ति के साथ अपनी व्यवस्था बना रखी थी। जिन विद्यार्थियों को रात्रि के समय पढ़ना होता था वे मोमबत्ती या दिये की मदद लेते थे।

आज यह सब बीते जमाने की बात हो चुकी है। न केवल घरों में हर समय बिजली होती है बल्कि रात्रि के समय स्ट्रीट लाइट से भी गलियां जगमग रहती हैं। खेतों में भी बिना शोर वाले ट्यूबवैल चलते रहते हैं। अधिकांश घरों में इन्वर्टर की व्यवस्था है।

जो ग्राम पंचायत अपने स्तर पर विकास कार्य नहीं करा पाई यह उनका आलस्य कहिए या नासमझी। जिन पंचायतों के प्रतिनिधि शिक्षित और जागरूक रहे उन्होंने अपने गांवों की गलियों में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए है और गलियों की सफाई के लिए नियमित सफाई कर्मचारी भी लगाए हैं। कई सरपंचों ने तो गांव में शानदार पार्क बनवाए हैं जहां सांझ ढले ग्रामीण टहलने आते हैं। पेयजल आपूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछवाई हैं।

वर्तमान सरकार में शिक्षा की गुणवत्ता पर उल्लेखनीय कार्य हुआ है। अनेक मॉडल संस्कृति स्कूल खोले गए हैं। पढ़ाई के प्रति शिक्षकों की मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले तीन-चार साल में राजकीय स्कूलों का परीक्षा परिणाम प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के मुकाबले बेहतर रहा है, जिसके चलते स्कूलों में छात्र एवं छात्राओं की संख्या में गुणात्मक वृद्धि हुई है। कौशल विकास केंद्रों में भी हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। गांव से अब प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल रहने वाले विद्यार्थी निकल रहे है। बेशक उन्हें कोचिंग के लिए निकटवर्ती शहर में जाना पड़ता हो। काबिलियत के आधार पर सरकारी नौकरियों की परंपरा शुरू होने के बाद ग्रामीण युवाओं में पढ़ने की सनक साफ देखी जा रही है।

सरकारी कामकाज के सरलीकरण के लिए गांव-गांव में अटल सेवा केंद्र खोले गए हैं। बैंकिंग व्यवस्था मजबूत हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की गुंजाइश है। खेल प्रतिभाओं के निखार के लिए ग्रामीण क्षेत्र में खेल के मैदान व योगशालाएं बनाई गई हैं।

गांव का जैसे-जैसे ढांचागत विकास हुआ है लोगों ने उसके अनुरूप जीवन शैली को ढाला है। गांव से शहर की ओर जाकर बसने की जो होड़-सी लगी थी उसमें कमी आई है। गांव अंदर से बेशक खाली हो रहे हों लेकिन बाहरी दिशा में बसावट बढ़ रही है।

हजारों गांवों में छोटे-छोटे बाजार विकसित हो रहे हैं। रोजमर्रा की जरुरत की चीजें यहां उपलब्ध हो जाती हैं। चटपटे व्यंजन जो शहरी सीमा तक थे वे अब गांवों में भी दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण युवक युवतियों की पोशाक शहरी संस्कृति से पीछे नहीं है। धोती-कुर्ता व खंडके वाले बुजूर्ग अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। घाघरी जम्फर का पहनावा लुप्तप्रायः है। महिलाएं साड़ी क्षेत्रवार पहनती हैं।

गांव की आधुनिक संस्कृति के बारे में जब एक बुजूर्ग से पूछा तो उन्होंने कहा- 'गाम में पहल्यां मकान कच्चे होया करते, पर माणस पक्के थे। आज मकान तो पक्के सैं, पर माणस कच्चे होण लाग गे।'

महाग्राम योजना

दस हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को विकसित करने के लिए 'महाग्राम योजना' शुरू की गई है। योजना के तहत इन गांवों मे शहरों की तर्ज पर सीवरेज सिस्टम स्थापित करना है। इसके लिए 129 गांवों का चयन किया गया है। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में 20 गांवों मे यह योजना पायलट के तौर पर प्रथम चरण में है, 38 गांवों में द्वितीय तथा 71 गांवों में तृतीय चरण में है।

सीवरेज व्यवस्था के साथ-साथ गांव में सोलिड ट्रीटमैंट प्लांट तथा बायोगैस प्लांट लगाने की संभावनाओं की तलाश की जा रही है ताकि पशुओं के गोबर का भी समाधान हो जाए। इससे लोगों को रसोई के लिए सस्ती बायोगैस उपलब्ध हो सकेगी।

योजना के तहत पेयजल आपूर्ति का मजबूत किया जाएगा। पेयजल 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से उपलब्ध कराने का लक्ष्य रहेगा। गांव की स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा।

राज्य सरकार का मकसद सर्वप्रथम लोगों के घरों में नल के माध्यम से पेयजल पहुंचाना है। निकासी के पानी को तालाबों में डालकर स्वच्छ करना तथा उसे कृषि में उपयोग करने की योजना भी रहेगी जिससे सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से फसलों को सिंचित किया जा सके। सर्वे के आधार पर शहरों में 38 मानकों के आधार पर 600 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 44 मानकों के आधार पर 15946 ऐसे तालाबों को चिन्हित किया गया है जिनका उद्धार किया जाना है।

आगामी 10 वर्षों में ऐसे करीब 16,000 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा जिनका पानी खराब हो चुका है या बेकार हो चुके हैं। हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, सिंचाई तथा विकास एवं पंचायत विभाग मिलकर इन तालाबों का सुधार करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने अधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों तक लोगों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के लगभग 600 स्वास्थ्य केन्द्रों को ई-उपचार प्रणाली से जोड़ा जाएगा इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल होंगे।

पंचायती राज संस्थाएं विकास कार्यों के लिए सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य 5 लाख रुपए तक के कार्य विभागीय स्तर पर करा सकेंगे। इससे ऊपर की राशि के निर्माण कार्य ई टेंडरिंग के माध्यम से ही करवाए जा सकेंगे।

फरवरी-मार्च में लगाई जाने वाली सब्ज़ियां

गर्मी के मौसम में सेवन की जाने वाली ज्यादातर सब्जियों की बुआई फरवरी मार्च के माह में होती है। इनमें खीरा, ककड़ी, करेला, लौकी, तोरई, पेठा, पालक, फूलगोभी, बैंगन, भिंडी, अरबी जैसी सब्जियां हैं।

खीरा

बागवानी वैज्ञानिकों के मुताबिक किसान पहले खेत में क्यारियां बनाएं व इसकी बुवाई लाइन में ही करें। लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 1.5 मीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी एक मीटर। बुआई के बाद 20 से 25 दिन बाद निराई - गुड़ाई करें। खेत में सफाई रखें और तापमान बढ़ने पर हर सप्ताह हल्की सिंचाई करें। समय समय पर खेत से खरपतवार हटाते रहें।

ककड़ी

ककड़ी की भूमि की तैयारी के समय गोबर की खाद डालें व खेत की तीन से चार बार जुताई करके सुहागा लगाएं। ककड़ी की बीजाई 2 मीटर चौड़ी क्यारियों में नाली के किनारों पर करनी चाहिए। पौधे से पौधे का अंतर 60 सेंटीमीटर रखें। एक जगह पर दो - तीन बीज बोएं। बाद में एक स्थान पर एक ही पौधा रखें।

करेला

करेले की सब्जियों के लिए हल्की दोमट मिट्टी अच्छी होती है। करेले की बुवाई दो तरीके से की जाती है - बीज से और पौधे से। करेले की खेती के लिए 2 से 3 बीज 2.5 से 5 मीटर की दूरी पर बोने चाहिए। बीज को बोने से पहले 24 घंटे तक पानी में भिगो लेना चाहिए इससे अंकुरण जल्दी और अच्छा होता है। नदियों के किनारे की ज़मीन करेले की खेती के लिए बढ़िया रहती है। कुछ अम्लीय भूमि में इसकी खेती की जा सकती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें इसके बाद दो - तीन बार हैरो या कल्टीवेटर चलाएं।

लौकी

लौकी की खेती कर तह की मिट्टी में हो जाती है लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। लौकी की खेती के लिए एक हेक्टेयर में 4.5 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। बीज को खेत में बोने से पहले 24 घंटे पानी में भिगोने के बाद टाट में बांध कर 24 घंटे रखें। करेले की तरह लौकी में भी ऐसा करने से बीजों का अंकुरण जल्दी होता है। लौकी के बीजों के लिए 2.5 से 3.5 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर चौड़ी व 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनानी चाहिए। इन नालियों के दोनों किनारे पर गरमी में 60 से 75 सेंटीमीटर के फासले पर बीजों की बुवाई करनी चाहिए। एक जगह पर 2 से 3 बीज 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं।

भिंडी

किसान भिंडी की अगेती किस्म की बुवाई फरवरी से मार्च के बीच करते हैं। इसकी खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है। भिंडी की खेती के लिए खेत को दो-तीन बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए और फिर पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। बुवाई कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार दूरी 25-30 सेमी और कतार में पौधे की बीच की दूरी 15-20 सेमी रखनी चाहिए। बोने के 15-20 दिन बाद पहली निराई-गुड़ाई करना जरुरी रहता है।

तोरई

हल्की दोमट मिट्टी तोरई की सफल खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नदियों के किनारे वाली भूमि इसकी खेती के लिए अच्छी रहती है। इसकी बुवाई से पहले, पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें इसके बाद 2 से 3 बार बार हैरो या कल्टीवेटर चलाएं। खेत की तैयारी में मिट्टी भुरभुरी हो जानी चाहिए। तोरई में निराई ज़्यादा करनी पड़ती है। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 1 से 1.20 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी एक मीटर होनी चाहिए। एक जगह पर 2 बीज बोने चाहिए। बीज को ज़्यादा गहराई में न लगाएं इससे अंकुरण पर फर्क पड़ता है। एक हेक्टेयर ज़मीन में 4 से 5 किलोग्राम बीज लगता है।

अरबी

अरबी की खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। इसके लिए जमीन गहरी होनी चाहिए। जिससे इसके कंदों का समुचित विकास हो सके। अरबी की खेती के लिए समतल क्यारियां बनाएं। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेमी. व पौधे से पौधे की दूरी 30 सेमी होनी चाहिए। इसकी गांठों को 6 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दें।

बैंगन

बैंगन की नर्सरी फरवरी में तैयार की जाती है और बुवाई अप्रैल में की जाती है। बैंगन की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। नर्सरी में पौधे तैयार होने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है खेत को तैयार करना। मिट्टी परीक्षण करने के बाद खेत में एक हेक्टेयर के लिए 4 से 5 ट्रॉली पक्का हुआ गोबर का खाद बिखेर दें। बैंगन की खेती के लिए दो पौधों और दो कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए।

पेठा

बागवानी अधिकारी सत्येंद्र के अनुसार पेठा कददू की खेती के लिए दोमट व बलुई दोमट मिट्टी सब से अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा यह कम अम्लीय मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है। पेठा की बुवाई से पहले खेतों की अच्छी तरह से जुताई कर के मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए और 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई कर के पाटा लगाना चाहिए। इसके लिए एक हेक्टेयर में 7 से 8 किग्रा बीज की जरूरत होती है।

संवाद ब्यूरो

नरमा की खेती से अच्छी खासी आय

नरवाना क्षेत्र के गांव खानपुर के काफी किसान परिवार नरमा की खेती कर लाखों रुपए की आय ले रहे हैं। किसान रमेश ने बताया कि वे 1990 से कपास की खेती करते आ रहे हैं। एक प्रकार से यहां खेती उनकी परंपरागत खेती है। उन्होंने सरकारी नौकरी करने की बजाय खेती को प्राथमिकता दी। इस वक्त उन्होंने 15 एकड़ जमीन में कपास की खेती लगाई है।

वे वर्ष में मात्र दो ही फसल लेते है। एक गेहूं की व दूसरी नरमा की। किसी रोग आदि से एक फसल में नुकसान हो जाता है तो दूसरी फसल में भरपाई हो जाती है। उन्होंने बताया कि सरकार ने नरमा का 55 सौ से ज्यादा एमएसपी दिया जिसके चलते उन्हें कपास की खेती में अच्छा खासा लाभ मिला है।

रमेश ने बताया कि मुख्य तौर पर वे 776 किस्म की फसल की खेती करते है। जिसमें एक एकड़ में 10 से 15 क्विंटल के करीब कपास की पैदावार हो जाती है। कपास की तुड़वाई के लिए एक एकड़ में 10 हजार रुपए से ज्यादा खर्च हो जाता है। अगर फसल सफेद सुंडी व गुलाबी मक्खी से बच जाये तो निश्चित रूप से अच्छी पैदावार होती है।

इस खेती में कम से कम किसान को बीमारी से बचाव के लिए 4 से 5 बार स्प्रे करना पड़ता है। वर्तमान में उनके पास 600 क्विंटल के करीब कपास का भंडार है सही दाम मिलने पर वे इसका विक्रय करेंगे।

सुरेंद्र सिंह मलिक

चावल व गेहूं का फसल चक्र बदलना ज़रूरी

जल संरक्षण और फसलों का विविधिकरण मौजूदा समय की मांग है। इसके लिए वैज्ञानिकों को ऐसी योजनाएं बनानी होंगी जिससे न केवल जल का संरक्षण हो बल्कि किसान फसल विविधिकरण को भी अपनाने के लिए सहमत हों। चावल व गेहूं के फसल चक्र को बदलना बहुत ज़रूरी है ताकि पानी का अधिक से अधिक संरक्षण किया जा सके।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉ. ए.के. सिंह ने हरियाणा व दिल्ली राज्यों के कृषि विज्ञान केंद्रों की राज्य स्तरीय योजना कार्यशाला में यह विचार रखा। वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली व चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के विस्तार शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में आईसीएआर की कृषि तकनीकी अनुप्रयोग संस्थान, जोन-2 जोधपुर (राजस्थान) के करीब 67 कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने कहा कि किसानों को नई कृषि तकनीकों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें अपनी कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके। इसके लिए वैज्ञानिकों का कर्तव्य बनता है कि वे किसानों को विश्वविद्यालय द्वारा विकसित आधुनिक तकनीकों जैसे जीरो टिलेज, लेजर लेवलिंग, बेड प्लांटिंग, सूक्ष्म एवं टपका सिंचाई आदि को अपनाने के लिए जागरूक करें। मिट्टी और पानी जैसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए संरक्षण कृषि पर जोर देना चाहिए। मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों के अतिरिक्त खनन की जांच करनी होगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्वों दोनों के असंतुलित उपयोग की मुख्य समस्या है। इसलिए, हमें फसल उत्पादकता को बनाए रखने के लिए उर्वरकों की सिफारिश और अपनाने के बीच की खाई को पाटना होगा। आवास की बढ़ती मांग, शहरीकरण और औद्योगीकरण के बढ़ते स्तर के कारण, उपजाऊ कृषि भूमि का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र गैर-कृषि उपयोग में स्थानांतरित किया जा रहा है।

सभी गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की कवायद

प्रदेश के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 'म्हारा गांव जगमग गांव' योजना के तहत 5,223 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति कराई जा रही है। वर्तमान में प्रदेश के 74 प्रतिशत गांवों को पूरी तरह जगमग किया जा चुका है। इन जिलों नामतः पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, रेवाड़ी और फतेहाबाद में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। 'म्हारा गांव जगमग गांव' योजना के तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं को 3,01,571 बिजली कनेक्शन दिए गए हैं।

बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के.दास ने बिजली निगमों के अधिकारियों को 'म्हारा गांव जगमग गांव' योजना के तहत प्रदेश के शेष 1,822 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति कराने के प्रयासों पर जोर देने के लिए कहा है।

अंबाला में प्रस्तावित आर्यभट्ट विज्ञान केन्द्र अपनी तरह का पहला विज्ञान केंद्र होगा। उनके नाम से बनाए जाने वाले इस केंद्र में आर्यभट्ट व अन्य वैज्ञानिकों के विषय में जानकारी दी जाएगी।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा संचालित 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में नकल की प्रवृत्ति पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के उद्देश्य से 'नकल रोको अभियान' प्रारंभ किया जा रहा है।

भूमि की उपयोगिता पर मंथन

प्रदेश की कृषि भूमि की भरपूर उपयोगिता को लेकर हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की की और से बैठक का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री मनोहरलाल, विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री श्री जे.पी. दलाल और सहकारिता राज्य मंत्री बनवारी लाल के अलावा उच्च अधिकारियों ने शिरकत की।

प्रदेश में इस समय 92 लाख एकड़ भूमि सत्यापित है जिसमें से लगभग 68 लाख भूमि पर खेती की जा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इसमें से बाकी 24 लाख एकड़ भूमि का भी पता लगाया जाना चाहिए कि उसका इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है। उन्होंने कहा कि 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' योजना के तहत फसल के सत्यापन का मैकेनिज्म मजबूत होना चाहिए।

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि केवल कृषि से किसानों की आय बढ़ाना मुश्किल है। इसके लिए बागवानी, फ्लोरीकल्चर, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे कृषि से जुड़े कार्यों को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पैरी-अर्बन कृषि के लिए शुरू में चार जिलों- सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए योजनाएं तैयार की जाएं ताकि वहां स्थानीय जरूरतों के हिसाब से खेती की जा सके।

हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का कार्य किसानों के कल्याण और उनकी आमदनी बढ़ाने से जुड़ी विभिन्न विभागों की योजनाओं की निगरानी करना और उनका सही ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाना है। साथ ही, इसका कार्य भूमिहीन किसानों समेत किसानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए नई स्कीमें संबंधित विभागों के ध्यान में लाना, उन्हें सुझाव देना और सिफारिशें करना भी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राधिकरण में कार्यकारी उपाध्यक्ष का प्रावधान किया जाना चाहिए जो एक सीईओ की तरह कार्य करे।

उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का कार्य कृषि को लाभकारी बनाने के लिए कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए एक व्यापक भूमि उपयोग नीति तैयार करने के साथ-साथ प्राकृतिक आपदा के चलते फसल के नुक़सान पर उचित राहत और मुआवजा दिलवाकर किसानों की पीड़ा को कम करना भी है। इसी तरह, इसका कार्य कृषि उत्पादकता बढ़ाने तथा उत्पादन लागत को कम करने के लिए भी सुझाव देना है।

संवाद ब्यूरो

तालाबों के जीर्णोद्धार में तेजी के निर्देश

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि प्रदेश के गंदे नालों के दूषित पानी को उपचारित कर मत्स्य पालन व सिंचाई के लिए इस्तेमाल किये जाने के कार्यों में तेजी लाए जाए। साथ ही बरसाती तालाबों की सफाई का भी विशेष ध्यान रखें तथा 30 जून तक उनको खाली कर सफाई का कार्य पूर्ण करें। सुधार के बाद तालाबों की देख-रेख के लिए स्थानीय स्तर पर युवकों की एक टीम गठित करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल तालाब बनाने तक ही सीमित न रहकर उनकी देख-रेख पर ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यदि किसी तालाब पर अतिक्रमण है तो उसे संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाएं ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।

वित्त वर्ष 2019- 20 और 2020-21 के दौरान विभिन्न स्कीमों के तहत कुल 905 तालाबों का सुधार-कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 756 तालाबों का कार्य पूर्ण होने के निकट है। वर्तमान में 18 मॉडल तालाबों में घरों से जो गंदा पानी आ रहा है उसे कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड टेक्नोलॉजी द्वारा उपचारित करने के बाद ही तालाबों में डाला जा रहा है तथा 2020-21 में प्रस्तावित 200 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य जल्द ही आरंभ किया जाएगा।

मसालों की खेती की संभावनाएं

यमुनानगर जिले के कलेसर क्षेत्र में मसाला खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, मसाले की खेती कम लागत में ज्यादा उत्पादन देती है व ज्यादा लाभकारी होती है ।

वन मंत्री कंवरपाल ने केरल राज्य का दौरा कर मसाला खेती का बारिकी से निरीक्षण व अध्ययन किया। जिन जगहों पर मसाला खेती की जाती है उन जगहों की भौगोलिक व प्राकृतिक स्थिति का जायजा लिया।

केरल में जिन जगहों पर मसाला खेती की जाती है, उससे मिलती जुलती परिस्थितियां हरियाणा के यमुनानगर जिले के कलेसर व पंचकूला के मोरनी क्षेत्र में हैं। हरियाणा में वन विभाग के माध्यम से मसाला खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मसाला खेती में काली मिर्च, तेजपत्ता, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, जावित्री, सुपारी, केला, अदरक, हल्दी आदि फसलें होती हैं। जायफल, दालचीनी, लौंग आदि मसालों के अधिक उत्पादन व लाभ लेने के लिए वृक्ष भी उगाए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान बहुत ही मेहनती व प्रगतिशील किसान हैं। मसाले की खेती को हरियाणा में वन विभाग के माध्यम से शुरू करवाने का अध्ययन व प्रयास जल्द से जल्द किया जाएगा, वन विभाग के माध्यम से हरियाणा राज्य मसालों की खेती में भी अग्रणीय भूमिका निभा सकता है।

शिवालिक की पहाड़ियों में गुलाब की खेती

शादी-विवाह, आध्यात्मिक अथवा सांस्कृतिक उत्सव में फूलों की काफी महत्ता है। खासकर गुलाब की, जिसे फूलों का राजा कहा जाता है। सौंदर्य के साथ उनकी महक वातावरण को बेजोड़ बना देती है। इन दिनों मोरनी की पहाड़ियां गुलाब से महक रही हैं। किसान कृष्ण कुमार व अन्य गुलाब की खेती से लाखों कमा रहे हैं। उन्होंने पॉलीहाऊस में यह खेती की है।

किसान कृष्ण कुमार 2010 से पॉलीहाउस तकनीक से गुलाब की खेती कर रहे है। उन्होंने बताया कि गुलाब एक ऐसा पौधा है जिसकी सारा साल बाजार में मांग रहती है। गुलाब एक जड़ी-बूटी भी है। जो सेहत से जुड़े कई फायदे देता है।

उन्होंने बताया गुलाब की खेती से पहले उनका अपना लकड़ी का आरा मशीन थी। 2009 में सब्जी की खेती करने की ठानी। इसके लिए पंचकूला बागवानी विभाग के जिला अधिकारी पीसी शर्मा से मिलना हुआ। जिन्होंने सब्जी के बजाय पॉली हाउस तकनीक द्वारा फूलों की खेती करने और इसके फायदे बताए। जिसके बाद 2010 में तीन एकड़ में पॉली हाउस लगाया और गुलाब की खेती शुरू की।

वे बताते हैं एक पॉली हाउस की उम्र 25 साल होती है। इसका ढांचा स्टील या लोहे से बनता है, प्लास्टिक की सीट से ऊपर का हिस्सा ढका जाता है। ये सीट 200 माइक्रान मोटाई वाली पारदर्शी एवं पराबैंगनी किरणों से बचाव करने वाली चादर होती है। तेज हवा चलने, और अत्यधिक गर्मी के कारण सीट कई बार खराब हो जाती है। जिसे हर दो से तीन साल में बदलना पड़ता है। ये प्रदेश में लगने वाला पहला पॉली हाउस है। पॉली हाउस में तेज धूप व बरसात से फूल व सब्जी के पौधों का बचाव होता है। साथ ही फसल के लिए अनुकूल वातावरण भी बना रहता है। उन्होंने बताया कि चार हजार वर्ग मीटर पॉलीहाउस लगाने पर 32 से 35 लाख रुपए खर्च आता है। सरकार द्वारा 65 फीसदी सब्सिडी दी जाती है।

पॉली हाउस से सब्जी व फूलों की खेती में अनेक फ़ायदे हैं। इससे उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ जाती है, साथ ही वर्ष भर उत्पादन लिया जा सकता है। पॉलीहाउस में बेमौसम सब्जी उगाने में कीटनाशकों पर खर्चा आधा हो जाता है व उत्पादन सामान्य खेती की तुलना में तीन-चार गुना ज़्यादा होता है।

विभाग द्वारा किसानों को खेती की नई-नई तकनीक और फसल विविधिकरण के लिए समय-समय पर प्रोत्साहित किया जाता है। फूलों की खेती लाभ का सौदा है। पंचकूला जिला में लगभग 60 एकड़ में किसान फूलों की खेती करते हैं। दरअसल इस क्षेत्र का मौसम फूलों की खेती के अनुकूल है। इसलिए यहां अधिक मात्रा में फूलों की खेती होती है। एक पॉली हाउस पर सरकार ने 65 फीसदी सब्सिडी देने का प्रावधान किया है।

डॉ अशोक कौशिक, जिला बागवानी विभाग अधिकारी, पंचकूला

गुलाब की मांग वर्षभर रहती है। कृष्ण ने बताया कि चंडीगढ़ में गुलाब की सेल हो जाती है। जहां से व्यापारियों द्वारा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में गुलाब की सप्लाई की जाती है। एक बंच (बॉक्स) पर 350 से 400 रुपए मिल जाते हैं। एक बंच में गुलाब की 20 स्टिक होती हैं। खासकर शादियों और नवरात्रों में गुलाब की मांग ज्यादा होती है। सीजन में मुनाफे के साथ साल में लाखों की कमाई हो जाती है। है। कोरोना काल में लॉकडाउन चलते काफी नुक़सान उठाना पड़ा था।

मनोज त्यागी

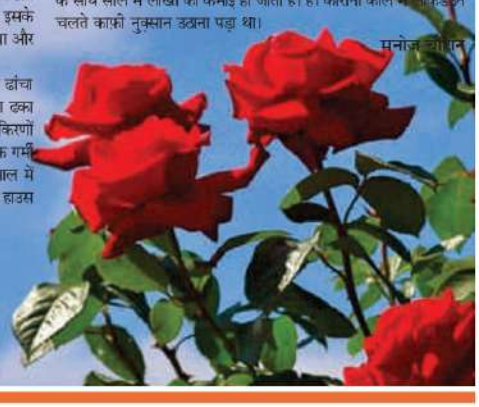

1857 की क्रांति में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सेनानियों की याद में अंबाला में विशाल स्मारक का निर्माण करवाया जा रहा है। हरियाणा सरकार 22 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस विशाल स्मारक के निर्माण पर 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

राइट टू सर्विस एक्ट के तहत सेवाएं देने में रेवाड़ी जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। एक लाख 13 हजार आवेदनों पर तय समय में कार्य करने पर स्कोर 10 में से 9.7 रहा है।

प्रदेश को मिलेगा भरपूर पानी : सीएम

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि प्रदेश में पानी की उपलब्धता हेतु किशाऊ डैम के लिए जल्द ही एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ लखवार और रेणुका डैम के लिए पहले ही एमओयू हो चुका है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की छठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण और जल का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। परंतु प्रदेश का अधिकांश हिस्सा डार्क जोन में तबदील होता जा रहा है, इसलिए केंद्र सरकार एसवाईएल, हांसी बुटाना लिंक नहर के मुद्दे पर हस्तक्षेप कर इसे सुलझाए ताकि हरियाणा को अपना पानी मिल सके।

कृषि क्षेत्र को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों के बेहतर व उचित उपयोग हेतु जिला स्तर पर फसल प्रणाली को कृषि-जलवायु परिस्थितियों के साथ जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

- धान की फसल के स्थान पर वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का, कपास, बाजरा, दालें, सब्जियां और फलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना शुरू की गई है।
- किसानों को फसल विविधिकरण अपनाने के लिए 7 हजार रुपए प्रति एकड़ का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश में 97,000 एकड़ भूमि पर धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों की बुवाई की गई है।
- प्रदेश सरकार जल संरक्षण को बढ़ावा देने पर बल दे रही है। इसके लिए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण और हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है।
- गैर-पोटेंबल उपयोग के लिए 25 प्रतिशत उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करने के उद्देश्य से उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की नीति लॉन्च की गई।
- राज्य में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो इरिगेशन एवं कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया।
- मानसून व वर्षा जल के उपयोग के लिए सिंचाई प्रणाली को पुनः व्यवस्थित किया जा रहा है और नहरी व्यवस्था का जीर्णोद्धार किया जा रहा है।
- देश में हरियाणा में गन्ना किसानों को सबसे अधिक 350 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य दिया जा रहा है।
- प्रदेश में चना, सरसों, सूरजमुखी, बाजरा और मक्का जैसी विभिन्न फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है।
- 17,216 हैक्टेयर क्षेत्र में मछली पालन किया जा रहा है, जिससे राज्य में 1.91 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ है। खारे पानी से प्रभावित क्षेत्रों में सफेद झींगा का उत्पादन किया जा रहा है, जिसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं।
- बागवानी किसानों के लिए 'मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना' शुरू की गई है जिसके तहत 20 फलों और सब्जियों को शामिल किया गया है।
- प्रदेश में सब्जी किसानों को जोखिम प्रति करने के लिए 'भावांतर भरपाई योजना' भी लागू की गई है।
- खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योग तथा निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। बारही और रोहतक में दो मेगा फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं।
- गन्नौर में लगभग 7 हजार करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार स्थापित किया जा रहा है।
- गुरुग्राम में फूल मार्केट, सेब के व्यापार की सुविधा के लिए पंचकूला में सेब मार्केट और सिरसा में मसाला मार्केट भी बनाई जा रही है।
- विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन कॉर्पोरेशन की स्थापना की जा रही है और पलवल से सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है।
- प्रदेश में पराली निस्तारण के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में 100 प्लांट लगाने की योजना है।

शिक्षा में सुधार के लिए उठाए अनेक कदम

नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल ने कहा कि शिक्षा सदैव प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रही है। शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि 3 से 6 साल के बच्चों के लिए 4 हजार प्ले वे स्कूल खोलने की सरकार की योजना पर कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा, सुपर 100 कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसमें सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को रेवाड़ी और पंचकूला में जेईई और एनईईटी के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग दी जा रही है। डिजिटल माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क टैब सुविधा प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि वर्कफोर्स के कार्यकौशल/ रिस्कीलिंग और अपस्किलिंग के लिए संसाधनों को मजबूती देने हेतु कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। 15,301 सक्षम युवाओं को हरियाणा कौशल विकास मिशन के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इसके अलावा, प्रदेश के सभी जिलों में जल्द ही 'स्किल गैप स्टडी' शुरू की जाएगी ।

युवाओं को रोज़गार

प्रदेश सरकार नौकरियां के अवसर मुहैया कराने पर विशेष ध्यान दे रही है। हाल ही में हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोज़गार विधेयक पारित किया गया है। वर्कफोर्स का डिजिटल डाटाबेस बनाया गया है। पिछले पांच वर्षों में पांच लाख युवाओं को रोज़गार मिला है। इसके अलावा, 105 ऑनलाइन जॉब फेयर/ प्लेसमेंट ड्राइव का भी आयोजन किया गया है।

विकसित होता आधारभूत ढांचा

प्रदेश में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए केएमपी के आस-पास हरियाणा रेल ऑर्बिटल परियोजना को लागू किया जा रहा है और केएमपी एक्सप्रेसवे का निरंतर सुधार किया जा रहा है। साथ ही, हिसार में एकीकृत विमानन हब और हरियाणा में दिल्ली मेट्रो के विस्तार की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

गांव समसपुर में दूध का कारोबार

प्रदेश का गांव समसपुर आत्मनिर्भरता की मिसाल है। अस्सी प्रतिशत ग्रामीण दूध का कारोबार करते हैं। यहां से दूध आस-पास के 40 गांव और शहर में सप्लाई होता है। समसपुर गांव धानेसर-पिहोवा मार्ग से ज्योतिसर गांव के रास्ते पड़ता है, जो अधिक पशुधन रखने के लिए भी प्रसिद्ध है।

करीब तीन हजार की आबादी वाला समसपुर छोटा अवश्य है लेकिन आत्मनिर्भरता के मामले में बड़ा है। गांव के हर घर में गाय या भैंस है। कुछ बड़े दुग्ध उत्पादक हैं तो कुछ छोटे स्तर पर दूध का व्यवसाय करते हैं। समसपुर में 4,000 के करीब पशु हैं और 28 दूधिये। सरकारी नौकरी में मात्र दो प्रतिशत ग्रामीण हैं।

किसान सौरभ सिंह खेती-बाड़ी के साथ दुग्ध उत्पादक हैं। सौरभ सिंह ने गांव में डेयरी बनाई है। वे पशुपालकों से दूध लेकर शहर में सप्लाई करते हैं। सौरभ सिंह पिछले 18 साल से दूध का कारोबार कर रहे हैं। इनका पूरा परिवार तड़के सांझ भैंसों को चारा डालने और दूध दोहने का कार्य करते हैं। बताया उनका 14 परिवारों का हमार बड़ा कुनबा है। जो 50 साल पहले अंबाला के कालपी से इस गांव में आकर बसा था। दादा मुंशी राम, तेलु राम और श्रवण राम तीन भाईयों का है ये कुनबा। सभी परिवार दूध का कारोबार करते हैं।

उनके पास मुरह्ा और एचएफ नसल की 20 गाय-भैंस हैं। उन्होंने बताया परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है। दूध के कारोबार में दूध बेचकर व खर्चा निकाल कर अच्छी खासी बचत हो जाती है। दूध शहर में 50 से 55 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिकता है। वे शहर में सीधे उपभोक्ताओं के पास बेचते हैं। किसी भी कंपनी को बेचते। लाभ सिंह ने बताया कि उनकी योजना अधिक से अधिक परिवारों को दूध उपलब्ध कराना है।

विक्रम सिंह भी पिछले 20 साल से दूध के व्यवसाय में लगे हैं। उनके पास 20 से ज्यादा पशुधन हैं। इसके अलावा वे अन्य ग्रामीणों से भी दूध एकत्र कर आगे शहर में बेचते हैं। उन्होंने बताया कि डेयरी एक ऐसा व्यवसाय है जो साल भर चलता है। घाटे की कम आशंका होती है। उन्होंने बताया कि वे गर्मियों में प्रतिदिन दो क्विंटल और सर्दियों में तीन क्विंटल दूध बेच देते हैं।

मनोज चौहान

देश के सभी नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिए भुगतान आवश्यक कर दिया गया है। बिना फास्टैग स्टीकर लगी गाड़ी को इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पार करने के लिए दोगुना चार्ज देना होगा।

देश में एक मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इस चरण के तहत 60 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इसके अलावा 45 साल की उम्र वाले उन लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी, जो बीमार हैं।

महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता

संगीता शर्मा

बेटियां परिवार के लिए बोझ नहीं है, उन्हें अच्छी परवरिश, शिक्षा एवं अवसर प्रदान करके कामयाब इंसान बनाया जा सकता है। महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं एवं बच्चों के विकास से संबंधित योजनाओं, नीतियों, विनियमों और कानून को राज्य में लागू करके बेटियों व महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है। विभाग द्वारा राज्य व केंद्र स्तर पर सीधे नियंत्रण में तथा इसके संरक्षण में कार्य कर रहे हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, हरियाणा महिला आयोग तथा हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को वित्तीय सहायता देकर तथा अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। 8 मार्च को 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' है। प्रस्तुत हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के कुछ अंश।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम

'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी 2015 को जिला पानीपत, हरियाणा से किया गया। जिसका उद्देश्य लड़कियों के जन्म के प्रति सकारात्मकता, शिक्षा और पोषण देने के लिए सामाजिक सोच में परिवर्तन लाना है। राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप अच्छे नतीजे सामने आये है। 2011 की जनगणना अनुसार राज्य का लिंग अनुपात 830 था जो कि दिसंबर 2020 तक बढ़कर 922 तक पहुंच गया है।

आपकी बेटी- हमारी बेटी योजना

के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को पहली बेटी के जन्म पर तथा सभी परिवारों को दूसरी बेटी के जन्म पर 21,000/- रुपए की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम में एकमुश्त जमा करवाई जाती है तथा बालिका को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने व अविवाहित होने पर लगभग 1.00 लाख की राशि उसके उपयोग के लिए दी जायेगी। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक खाता खोला जा सकता है।

किशोरियों के लिए योजना

11-14 वर्ष की आयु वर्ग की केवल स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रत्येक ग्रामीण खंड की तीन बालिकाओं को क्रमशः 8,000 रुपए, 6,000 रुपए, 4,000 रुपए तथा 10+2 कक्षा की परीक्षा में क्रमशः 12,000 रुपए, 10,000 रुपए, 8,000. रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाते है।

महिलाओं के लिए ख़ास योजनाएं

उत्पीड़न से सुरक्षा

राज्य सरकार महिलाओं को कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने एवं गौरव के साथ कार्य करने के अधिकार के लिए वचनबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 लागू किया गया है। सभी सरकारी विभागों, बोर्डों एवं निकायों में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

इस योजना को 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013' के प्रावधानों के अनुसार सभी जिलों में लागू किया गया है जिसमें केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर 60:40 की दर से खर्चा किया गया। योजना के अंतर्गत गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को 5,000 रुपए की राशि तीन किस्तों में दी गई।

वन स्टॉप केंद्र 'सखी'

पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा सुविधा, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, मानसिक एवं सामाजिक काउंसलिंग, अस्थाई आवासीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वन स्टॉप केंद्र की स्थापना की गई है। राज्य में महिलाओं के लिये वन स्टॉप केंद्र 'सखी' की स्थापना महिला आश्रम, करनाल में की गई है। उपरोक्त के अलावा वन स्टॉप केंद्र जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, रेवाड़ी, भिवानी व नारनौल में भी स्थापित किए जा चुके हैं।

> हरियाणा सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान तथा सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। लिंगानुपात में सुधार तथा हर क्षेत्र में महिलाओं की बढ़चढ़कर भागीदारी इसका ताज़ा प्रमाण है।
>
> कमलेश ढांडा, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, हरियाणा

ओलंपिक कैंप में हरियाणा की 21 महिला बॉक्सर

हरियाणा की महिला बॉक्सर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। 16 फरवरी से 31 जुलाई तक दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित होने वाले ओलंपिक कैंप में देशभर की 37 मुक्केबाज प्रैक्टिस कर रही हैं जिनमें अकेले हरियाणा से 21 महिला बॉक्सर हैं।

कैंप में रोहतक की छह और भिवानी की पांच मुक्केबाज शामिल हैं। यह हरियाणा प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि यहां की बेटियां हरेक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। ग्रामीण परिवारों से बेटियां आगे बढ़ रही हैं।

हरियाणा की तरफ से मंजू रानी, मोनिका, आरती, ज्योति, अनामिका हुड्डा, मीनाक्षी, शिक्षा, मनीषा, साक्षी ढांडा, सोनिया लाठर, सोनिया चहल, जैस्मिन लंबोरिया, शशि चोपड़ा, प्रवीण हुड्डा, जॉली फोगाट, अमृता अहलावत, पूजा बोहरा, पूजा सैनी, सुषमा यादव, अनुपमा कुंडू, आदि शामिल हैं। ओलंपिक कैंप को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह बना हुआ है।

खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों के खेलों के प्रति आकर्षण का पूरा श्रेय राज्य सरकार की खेल नीति को जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी को तैयारी के लिए पांच लाख रुपए एडवांस देने की घोषणा से खिलाड़ियों में नया जोश पैदा हुआ है।

मनिका को बनाया 'ब्रांड एम्बेसडर'

'फेमिना मिस ग्रेंड इंडिया 2020' की विजेता मनिका श्योकंद को राज्य सरकार की ओर से 'मेरा पानी-मेरी विरासत योजना' का ब्रांड एम्बेसडर बनने की पेशकश की गई जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया।

उन्होंने इस प्रतियोगिता में 'मिस फोटोजेनिक' का टाइटल जीतकर भी प्रदेश का नाम रोशन किया है।

इससे पहले, मानुषी छिल्लर और मीनाक्षी ने भी इसी तरह की सौंदर्य प्रतियोगिता में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। मानुषी छिल्लर वर्ष 2017 में विश्व सुंदरी बनी, जबकि मीनाक्षी वर्ष 2018 में रनरअप रही।

मुख्यमंत्री मनोहरलाल से बातचीत करते हुए मनिका ने भविष्य में पर्यावरण संरक्षण पर काम करने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए न केवल जल, वायु और मिट्टी का बचाना जरूरी है, बल्कि उपयोग किये गये उत्पादों का सही से निपटान करना भी जरूरी है। विशेषकर, सैनेटरी पैड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसको बनाने में प्लास्टिक की अपेक्षा बॉयोडिग्रेडेबल सामग्री जैसे कि कॉटन, बांस, केला, जूट आदि का उपयोग किया जाना चाहिए।

इस पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे इस बारे उद्यमियों से विचार-विमर्श कर कारगर कदम उठाएं। मुख्यमंत्री ने मनिका श्योकंद की पर्यावरण संरक्षण के प्रति रुचि को देखते हुए उन्हें मनिका मूल रूप से जींद के उचाना कलां से हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नेटबॉल की खिलाड़ी रही है। सेक्टर-7 के केबीडीएवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल से स्कूलिंग हुई है। कैमिकल इंजीनियर में ग्रेजुएशन की है। पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के यूआईएफटी डिपार्टमेंट से पासआउट है।

बचपन से मॉडलिंग का शौक

मूल रूप से जींद के उचाना कलां और वर्तमान में पंचकूला निवासी मनिका श्योकंद को बचपन से मॉडलिंग करने का शौक था, लेकिन उसको नजरअंदाज करके अपनी पढ़ाई को देखते हुए मार्केटिंग की नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन दो साल पहले अपनी बड़ी बहन के कहने पर नौकरी छोड़कर मॉडलिंग में कदम रखा। सबसे पहले मनिका ने 'मिस हरियाणा' का खिताब जीता था। उसके बाद मुंबई में 'फेमिना मिस ग्रेंड इंडिया 2020' प्रतियोगिता में भाग लिया। यहां उनका चयन टॉप 15 प्रतियोगी में हुआ। उन्होंने विश्वास, काबिलियत के बलबूते 'मिस इंडिया' का ख़िताब अपने नाम कर लिया। उन्होंने बताया कि सौंदर्य प्रतियोगिता के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला और अपनी प्रतिभा को निखारा। अपने ऊपर विश्वास तो था कि मिस इंडिया का ख़िताब हासिल कर लूंगी, लेकिन परिणाम के दौरान बहुत घबराहट थी, जैसे विजेता नाम की घोषणा हुई तो मेरे खुशी से आंसू छलक गई और माता-पिता की खुशी व आंसू देखकर मेरा हौसला बहुत बढ़ गया।

मनिका के पिता सूरजमल श्योकंद व माता ममता ने बताया कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है जिससे फेमिना मिस ग्रेंड इंडिया -2020 का ताज मिला है। बेटी भी बेटो से कम नहीं होती है। कभी भी बेटी को उनके परिवार ने बेटे से कम नहीं समझा है।

भारत रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए मॉरीशस को दस करोड़ डॉलर देगा। दोनों देशों के बीच इस राशि की कर्ज़ सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देश चाहते हैं कि हिंदमहासागर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो।

सुदूर इलाके में जहां कहीं भी कोई नागरिक रहता है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना उनकी सरकार का कर्त्तव्य है। हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं: पीएम एनके मोदी

सरस्वती के लिए भागीरथ प्रयास

संवाद ब्यूरो

हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से आदि बद्री से लेकर कैथल तक सरस्वती चैनल पर स्थित तीर्थ स्थलों और गांवों को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे है।

राज्य सरकार ने सरस्वती नदी के पुनरोद्धार के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत आदि बद्री में सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय का निर्माण किया जाएगा। साथ ही, कैनथल सप्लाई चैनल द्वारा मारकंडा नदी और सरस्वती नदी को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने पर लगभग 894 हैक्टेयर मीटर बाढ़ के पानी को सरस्वती जलाशय में मोड़ा जा सकेगा। केंद्रीय जल आयोग द्वारा डैम की डिजाइनिंग का काम किया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव-2021 के दौरान 'सरस्वती नदी-नए परिप्रेक्ष्य और विरासत विकास' विषय पर आयोजित एक सेमिनार में मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज सरस्वती नदी की खोज से जुड़े कार्यों में जो प्रगति हुई है, उसका श्रेय काफी हद तक स्वर्गीय श्री दर्शन लाल जैन को जाता है।

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि सरस्वती नदी के अस्तित्व को लेकर जो शंकाएं थीं, उन सबका समाधान हो चुका है और इसके प्रवाह के वैज्ञानिक प्रमाण मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा को विश्वभर में वैदिक संस्कृति के उद्गम स्थल के नाम से जाना जाता है। इसका श्रेय यहां बहने वाली मां सरस्वती को ही जाता है जिसने अपनी गोद में इस संस्कृति का पालन-पोषण किया।

ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्त्व से ओत-प्रोत महाभारत का युद्ध भी सरस्वती के ही तट पर धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। भगवान श्रीकृष्ण ने ज्ञान, भक्ति व कर्म की अमर कृति श्रीमद्भगवद्गीता का ज्ञान भी इसी पावन भूमि पर दिया था।

रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिबद्री से सिरसा तक कुरुक्षेत्र, पिहोवा, हिसार, राखी-गढ़ी, फतेहाबाद और सिरसा में राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन सर्किट के विकास से इन क्षेत्रों में तीर्थाटन के नए अवसर सृजित होंगे, जिसके परिणामस्वरूप रोज़गार और व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे। सरस्वती नदी के साथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से मूलभूत सुविधाओं में सुधार होगा और इस क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। साथ ही, सरस्वती नदी के तट पर वनीकरण से हमें पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

सरस्वती के अहम पहलू

- महाभारत में मिले वर्णन के अनुसार सरस्वती हरियाणा में यमुनानगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा-सा नीचे आदिबद्री नामक स्थान से निकलती थी। आज भी लोग इस स्थान को तीर्थस्थल मानते हैं।
- वैदिक और महाभारत कालीन वर्णन के अनुसार इसी नदी के किनारे ब्रह्मावर्त था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहां जलाशय है।
- वर्तमान में इसरो, जी.एस.आई., एस.ओ.आई., ए.एस.आई., ओ.एन.जी.सी., एन.आई.एच. रुड़की, बी.ए.आर.सी., सरस्वती नाड़ी शोध संस्थान जैसे 70 से अधिक संगठन सरस्वती नदी विरासत के अनुसंधान कार्य में लगे हैं।
- इसरो, हरसैक, सीजीडब्ल्यूबी और अन्य वैज्ञानिक संगठनों द्वारा सरस्वती नदी के पुरापाषाण काल का परिसीमन और मानचित्रण तैयार किया गया है।
- अनुसंधान, दस्तावेज़ों, रिपोर्टों और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह साबित हो गया है कि सरस्वती नदी के प्रवाह भूगर्भ में अभी भी आदिबद्री से निकल रहे हैं और गुजरात के कच्छ तक चल रहे हैं।
- भारतीय सर्वेक्षण विभाग के पुराने मानचित्रों के अनुसार सरस्वती नदी योजना को अंतिम रूप दिया गया है।
- हरियाणा सरस्वती हैरिटेज विकास बोर्ड ने अनुसंधान गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न संगठनों के साथ पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इनमें तेल और प्राकृतिक गैस निगम, नई दिल्ली, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हैदराबाद, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की और भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, लखनऊ शामिल हैं।

सरस्वती के साथ सोम व घग्गर का संगम

सिंधु सभ्यता के उत्थान और पतन को समझने के लिए भी सरस्वती नदी की उत्पत्ति व विलुप्ति का पता लगाना अति आवश्यक है। सरस्वती पर शोध व अन्य कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015 में 'सरस्वती हैरीटेज विकास बोर्ड' की स्थापना की गई थी। इस बोर्ड का मुख्य कार्य इस पवित्र नदी का पुनरोद्धार और संपूर्ण विश्व के समक्ष भारतीय सांस्कृतिक विरासत को उजागर करना है। सरस्वती नदी का पुनरूद्धार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पुरातात्विक विरासत से संबंधित राष्ट्रीय गौरव का विषय है। सरस्वती नदी का पुनरोद्धार प्राचीन सरस्वती विरासत को पुनर्जीवित करेगा और दुनिया की सबसे पुरानी सरस्वती नदी सभ्यता को दुनिया के सामने लाएगा। सरस्वती नदी में गिरने वाले सभी 23 छोटे चैनलों व नालों को सरस्वती नदी का नाम दिया गया है। इससे सरस्वती नदी के तीर्थों का महत्त्व और अधिक बढ़ जाएगा। यह परियोजना ऐसे सभी स्थानों को विकसित करने के लिए भी लाभदायक होगी, जहां सरस्वती नदी और उसकी विरासत के प्रमाण मौजूद हैं। सरस्वती नदी में जल के बारहमासी प्रवाह से भूजल स्तर का पुनर्भरण होगा, क्योंकि हरियाणा का अधिकांश क्षेत्र डार्क जोन में बदल गया है। इसके अलावा, सरस्वती नदी के साथ सोम और घग्गर, दोनों नदियों को परस्पर जोड़ने का कार्य चल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई में सुधार व भूजल रिचार्जिंग का लाभ मिलेगा।

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री

कविता

नीली नदी एक बहती है

चुपचाप..
सरस्वती है वो.. दिखती नहीं..
बस दुखती रहती है..

सब यूं याद करते है जैसे बीत गई हो...
नहीं खबर.. न परवाह किसी को भी कि..
थकियाई गई है सिमट जाने को
अब हर ओर से खुद को बटोर..
अकेली ही बहती रहती है..

नित नए.. रंग बदलते जहाँ में..
अपना पुरातन मन लिए एक गठरी में..
बदहवास भागी थी..
कहीं जगह मिले...

हर उस हाथ को चूम लिया
जिसने अपना हाथ भिगोया..
फिर ठगी देखती रही..
राही उठ चल दिया था..

पानी पी कर उठे मुसाफिर..
कब रुके हैं नदियों के पास?
उन्हें सफर की चिन्ता और मंजिलों की तलाश है
नदियाँ बस प्यास बुझाती है
यात्रा की क्लान्ति सोख कर
पुनर्नवा कर देती हैं...

और जाने वाले को..
स्नेह से ताकती रहती है
जानती है.. वो लौटेंगे..
फिर से चले जाने के लिए..

पर सरस्वती सूख गई..
पृथु-पुत्रों का रूखपन सहन नहीं कर सकी
माँ की कोख में लौट गई..
अब विगत से बहुत दूर..
चुपचाप बहती रहती है...

दिखती नहीं.. सिर्फ दुखती रहती है..

- अपर्णा

साहित्य के लिए 'सम्मान'

हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यकार सम्मान योजना वर्ष 2017, 2018 तथा 2019 के लिए विभिन्न सम्मानों हेतु साहित्यकारों का चयन कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल ने बताया कि अकादमी अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा इन सम्मानों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 के लिए अकादमी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किए जाने वाले **'आजीवन साहित्य साधना सम्मान'** (7 लाख रुपए) हेतु दिल्ली निवासी वरिष्ठ साहित्यकार एवं चिंतक डॉ. कमल किशोर गोयनका का, वर्ष 2018 के लिए दिल्ली निवासी वरिष्ठ लेखक एवं समालोचक डॉ. सुरेश गौतम तथा वर्ष 2019 के लिए चंडीगढ़ निवासी वरिष्ठ साहित्यकार एवं चिंतक माधव कौशिक का चयन किया गया है।

डॉ अग्रवाल ने बताया कि 'महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान' (5 लाख रुपए) के अंतर्गत वर्ष 2017 के लिए रोहतक निवासी डॉ. पूर्णचन्द शर्मा, वर्ष 2018 के लिए भी रोहतक निवासी मधुकांत तथा सोनीपत निवासी डॉ. संतराम देशवाल एवं वर्ष 2019 के लिए फरीदाबाद निवासी डॉ. सुदर्शन रत्नाकर एवं गुरुग्राम निवासी चन्द्रकांता का चयन किया गया है।

उन्होंने बताया कि 'पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान' (2.50 लाख रुपए) के अंतर्गत वर्ष 2017 के लिए रोहतक निवासी डॉ. रामफल चहल, वर्ष 2018 के लिए करनाल निवासी डॉ. महावीर प्रसाद शर्मा तथा सिरसा निवासी डॉ. शील कौशिक तथा वर्ष 2019 के लिए कुरुक्षेत्र निवासी डॉ. लालचन्द गुप्त मंगल का चयन किया गया है।

इसी प्रकार, 'बाबू बालमुकुंद गुप्त सम्मान' (2 लाख रुपए) के अंतर्गत वर्ष 2017 के लिए करनाल निवासी डॉ. अशोक भाटिया तथा कुरुक्षेत्र निवासी डॉ. दिनेश दधीचि, वर्ष 2018 के लिए सिरसा निवासी डॉ. रूप देवगुण तथा डॉ. राजकुमार निजात एवं वर्ष 2019 के लिए करनाल निवासी गुलशन मदान तथा गुरुग्राम निवासी डॉ. घमण्डीलाल अग्रवाल का चयन किया गया है।

'लाला देशबन्धु गुप्त सम्मान' (2 लाख रुपए) के अंतर्गत वर्ष 2017 के लिए अंबाला निवासी विकेश निझावन, वर्ष 2019 के लिए कैथल निवासी श्री सुरेश जांगिड का चयन किया गया है। पण्डित लखमीचन्द सम्मान (2 लाख रुपए) के अंतर्गत वर्ष 2019 के लिए जींद निवासी रामफल गौड़ का चयन किया गया है। जनकवि मेहर सिंह सम्मान (2 लाख रुपए) के अंतर्गत वर्ष 2017 के लिए कुरुक्षेत्र निवासी डॉ. महासिंह पुनिया, वर्ष 2018 के लिए रेवाड़ी निवासी सत्यवीर नाहड़िया तथा वर्ष 2019 के लिए पानीपत निवासी डॉ. बालकिशन शर्मा एवं कैथल निवासी डॉ. राजेन्द्र बडगूजर, का चयन किया गया है।

डॉ अमित अग्रवाल ने बताया कि 'हरियाणा गौरव सम्मान' (2 लाख रुपए) के अंतर्गत वर्ष 2017 के लिए दिल्ली निवासी डॉ. सारस्वत मोहन मनीषी तथा वर्ष 2018 के लिए विनोद बब्बर का चयन किया गया है।

उन्होंने बताया कि 'आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान' (2 लाख रुपए) के अंतर्गत वर्ष 2017 के लिए फरीदाबाद निवासी श्री मनजीत सिंह एवं वर्ष 2018 के लिए नई दिल्ली निवासी श्री महेन्द्र शर्मा तथा वर्ष 2019 के लिए सोनीपत निवासी डॉ. अशोक बत्रा का चयन किया गया है।

'श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान' (2 लाख रुपए) के अंतर्गत वर्ष 2017 के लिए रोहतक निवासी डॉ. रोहिणी अग्रवाल तथा हिसार निवासी डॉ. शमीम शर्मा, वर्ष 2018 के लिए चंडीगढ़ निवासी धीरा खण्डेलवाल एवं वर्ष 2019 के लिए सोनीपत निवासी कमलेश मलिक तथा करनाल निवासी डॉ. ज्ञानी देवी का चयन किया गया है।

'स्वामी विवेकानन्द स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान' वर्ष 2017 के लिए सोनीपत निवासी डॉ. ज्योति, वर्ष 2018 के लिए कैथल निवासी डॉ. राजेश भारती तथा वर्ष 2019 के लिए जींद निवासी डॉ. शिवा का चयन किया गया है।

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com